दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2004/15489 www.uvindianews.com प्रधान सम्पादक: सत्येन्द्र सिंह

वर्ष : 17 | अंक : 7 | गाजियाबाद, जुलाई, 2021 | मूल्य : 4 रूपया | पृष्ठ : 04 | E-mail : udyogviharnp@gmail.com

सबसे अधिक 113 केंद्रों पर 18 हजार लोगों को टीका लगा

नोएडा। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार को 17908 लोगों को टीका लगाया गया। इसमें दादरी और जेवर में नियर टू होम टीकाकरण भी शामिल है। इससे पहले 24 जून 21 हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। जेवर और दादरी में नियर टू होम टीकाकरण अभियान की शुरूआत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में लगभग 25,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा था। लिहाजा पहली बार जिले में 113 सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण हुआ। 18-44 आयुवर्ग में 11629 लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। 593 ने दूसरी खुराक ली। 60 से अधिक आयुवर्ग में 722 ने पहली और 1005 ने दूसरी खुराक लगवाई। 44-59 आयुवर्ग में 1918 ने पहली खुराक ली। 2003 लोगों को दूसरी खुराक दी गई।

कोरोना लाइव

30,619,932	29,752,294	403,310	184,969,547
मामले (भारत)	मरीज ठीक हुए	कुल मौतें	मामले (दुनिया)

नई आबकारी नीति : शराब की दुकानों की बदलेगी सूरत, रात 3 बजे तक खुलेंगे क्लब, होटल और रेस्टोरेंट के बार

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजस्व को बढ़ाने और शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए अपनी नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी है। दिल्ली में शराब की दुकानों की शक्ल भी अब बदल जाएगी। सरकार की नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानें खुली जगह वाली होंगी, ये एयर कंडीशन युक्त होंगी, जहां धक्का- मुक्की नहीं होगी और लोग आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे। ग्राहकों को अब शराब के ठेकों में वॉक-इन का अनुभव देने, बीयर बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने और होटल, क्लब एवं रेस्तरां के बार को देर रात तीन बजे तक खोलने की अनुमति देने जैसे कदम उठाए गए हैं। आबकारी नीति 2021-22 को सार्वजनिक किया गया, जिसमें कहा गया कि दुनिया के जिन शहरों में लोग सर्वाधिक घूमने जाते हैं, उनमें दिल्ली 28वें स्थान पर है और भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहीं आते हैं। इसमें कहा गया है कि शराब राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि, नीति दस्तावेज में शराब की होम डिलीवरी (घर तक पहुंचाने की सुविधा) और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है। शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था।

दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने की अनुमति नहीं

नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के खुदरा कारोबार से बाहर हो जाएगी, जिससे राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के अनुसार, शहर में शराब के प्रत्येक ठेके पर ग्राहकों को वॉक-इन की सुविधा मिलेगी। यानी अब ठेकों में ब्रांड के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांड की शराब चुन सकेंगे। वातानुकूलित खुदरा दुकानों में कांच के दरवाजे होंगे। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली की नई आबकारी नीति, 2021 में बीयर बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है।

इसके तहत दिल्लीवासी अब इन छोटी इकाइयों से ताजा ड्राट (खुली) बीयर ले सकते हैं। नीति के तहत बीयर बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बीयर की बिक्री की अनुमति दी गई है। नए सुधारों के तहत, होटल, रेस्तरां और क्लब में बार को देर रात तीन बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। इनमें वे लाइसेंसधारक शामिल नहीं हैं, जिन्हें शराब की चौबीसों घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है।

मोदी कैबिनेट से थावरचंद गहलोत की हुई छुट्टी, कई राज्यों में नए गवर्नर

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

नई दिल्ली। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा कई राज्यों में नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं तो कई स्थानों पर फेरबदल हुए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक हरि बाबू कमभमपति को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा मंगूभाई छगनभाई पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को राज्यपाल बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा कई राज्यों में गवर्नर बदले भी गए हैं। अब तक मिजोरम के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल रहे पीएस श्रीधरन को अब गोवा का गवर्नर बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को अब त्रिपुरा भेजा गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रहे रमेश बैस को झारखंड भेजा गया है। वहीं हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अब हरियाणा भेजा गया है। थावरचंद गहलोत को कैबिनेट से हटाने का फैसला ऐसे वक्त में हुआ है, जब मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं की जा रही हैं। कैबिनेट विस्तार में यूपी समेत कई चुनावी राज्यों और हाल ही में राज्य नेतृत्व से बेदखल हुए नेताओं को जगह दी जा सकती है। इन नेताओं में असम के पूर्व सीएम सर्वानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं। हालांकि अब तक औपचारिक तौर पर कैबिनेट विस्तार या फिर फेरबदल को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं की गई है। लेकिन थावरचंद गहलोत को मंत्री पद से हटाने से साफ है कि सरकार फेरबदल और विस्तार की तैयारी में है। यह उसकी शुरूआत भर है। इससे पहले आज शाम को पीएम नरेंद्र मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा समेत कई अहम नेताओं के साथ मीटिंग थी, जिसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है।

एक साल से एक ही थाने चौकी में जमे सब इंस्पेक्टर की होगी छुट्टी

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

गाजियाबाद। डीआईजी/एसएसपी अमित पाठक कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से हर संभव कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक साल से एक ही थाने चौकी में जमे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की लिस्ट बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि ऐसे लोगों की जल्द लिस्ट तैयार कराकर उन्हें दूसरे थानों में रवानगी कराई जाएगी। दरअसल डीआईजी अमित पाठक को आए हुए 2 महीने से अधिक का समय जनपद में हो गया और जनपद एक हाईटेक सिटी होने के चलते क्राइम का ग्राफ भी हाईटेक तरीके से होता दिखाई देता है। यानी कि कई बड़ी घटना होने के बाद डीआईजी अमित पाठक, एसपी देहात ईरज राजा और एसपी सिटी निपुण अग्रवाल एवं ज्ञानेंद्र सिंह कानून व्यवस्था के साथ कोई भी ढिलाई बरतना देखना नहीं चाहते। इसी उद्देश्य के चलते जल्द ही ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर एक बार फिर शुरू होने वाला है। पुलिस सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि डीआईजी अमित पाठक और एसपी देहात की डॉक्टर ईरज राजा कुछ पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। इसी उद्देश्य के

डीआईजी अमित पाठक कानून व्यवस्था को लेकर कर रहे मजबूती के साथ प्रयास

चलते कुछ पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर एवं इंस्पेक्टर एक साल से अधिक होने पर एक की थाने और चौकी पर जमे है उसके बावजूद भी क्राइम के ग्राफ पर लगाम नहीं लग पा रही। डीआईजी अमित पाठक और एसपी देहात की ईरज राजा ईमानदार होने के साथ-साथ कार्य कुशल भी हैं। जिसके चलते वह कानून व्यवस्था में कोई भी दिलाई बरतना देखना नहीं चाहते और उन्होंने जल्द ऐसे पुलिस कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर उन्हें दूसरे थाने में रवानगी कराने का प्रयास तेज कर दिए है। सूत्रों ने तो यहां तक बताया कि कुछ पुलिस विभाग के कर्मचारियों को गैर जनपद का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। लिहाजा डीआईजी अमित पाठक ने पूर्व में नौ इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र बदलकर कुछ हद तक कानून व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया तो वहीं अभी कुछ थानों में जमें थाना प्रभारियों की भी लिस्ट तैयार की जा रही है।

जीडीए सचिव की डीएम से की शिकायत

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

गाजियाबाद। पिछले सप्ताह वैशाली कॉलोनी में जीडीए मकान की छत भरभरा कर गिर जाने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में गुस्सा बढ़ गया है. जीडीए के प्रति लोगों के आक्रोश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी के सामने लोगों ने जीडीए अधिकारियों को खूब भला बुरा कहा. जीडीए का विरोध कर रहे लोगों ने डीएम आरके सिंह से जीडीए सचिव की शिकायत की और कहा कि सचिव संतोष कुमार राय लोगों की शिकायतों का समाधान कराने के बजाय उनके जख्म पर नमक रगड़ रहे हैं. डीएम ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान कराया जाएगा। वैशाली सेक्टर-1 हाउस नंबर 166 सी कामना वैशाली मैं पिछले सप्ताह एक मकान का पूरा छत लेंटर सहित नीचे गिर गया. मकान में उत्तराखंड का एक परिवार रहता है. गनीमत रही कि जिस समय छत गिरा उस समय कमरे से परिवार के लोग बाहर चले आए थे नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था. जिस मकान में हादसा हुआ वह जीडीए द्वारा निर्मित है. घटना के बाद जीडीए के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. भाजपा पार्षद मनोज गोयल के नेतृत्व में जब लोगों ने जीडीए सचिव से दोबारा छत की लेंटर डालने की मांग की तो सचिव ने उसे अनसुना कर दिया. लोगों के काफी विरोध के बाद जीडीए सचिव ने कहा

कि वह दिखाएंगे और संभव होगा तो कुछ मरम्मत कार्य करवा देंगे. जीडीए सचिव के इस रवैया से लोगों में गुस्सा है। जिस मकान का छत गिरा है उसके आसपास के लोगों में भय व्याप्त है ऊपर के रहने वाले लोगों में डर बना हुआ है कुछ लोगों ने अपने मकान में रहना छोड़ दिया है उन्हें डर है कि कहीं उनके मकान का भी छत ना गिर जाए। वैशाली सेक्टर 1 में वृक्षारोपण कार्यक्रम में आए जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह को इस विषय से अवगत कराते हुए जीडीए सचिव संतोष कुमार राय के रवैए की शिकायत की। क्षेत्रीय पार्षद मनोज गोयल मैं जिलाधिकारी के समक्ष स्थानीय लोगों की पीड़ा को रखते हुए कहा कि जीडीए सचिव का रवैया लोगों के जख्म पर नमक रगड़ने जैसा है. विदित हो कि जीडीए सचिव संतोष कुमार राय पिछले कई वर्षों से जीडीए में जमे हुए हैं और कई बार इनकी कार्यशैली को लेकर उंगली उठ चुकी है. जीडीए सचिव पर आरोप लगते रहे हैं कि वाह लोगों की शिकायतों पर गंभीरता नहीं दिखाते हैं और परेशान व पीड़ितों की मदद करने के बजाय उन्हें हशशङ्ख दिखाते हैं. विदित हो कि कुछ माह पूर्व जीडीए में भ्रष्टाचार का एक बड़ा खुलासा हुआ था जिसमें यह बात सामने आई थी की अवैध निर्माण के बदले जीटीए के प्रवर्तन विंग द्वारा प्रति लेंटर एक एक लाख लिया जाता है. इस प्रकरण में जीडीए अधिकारियों की बड़ी क्रिकेटिंग हुई थी।

जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश भी जीडीए के कई अधिकारियों की कार्यशैली से काफी असंतुष्ट हैं. जीडी उपाध्यक्ष ने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन भी बनाया था लेकिन कोरोना काल में उनका पूरा ध्यान शहर वासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने पर लगा रहा. जीडी उपाध्यक्ष ने प्रभारी जिलाधिकारी के रूप में प्रभावी ढंग से गाजियाबाद में करो ना के प्रभाव को कंट्रोल किया।

उद्योग विहार

निष्पक्ष पाक्षिक समाचार पत्र

श्रम–जगत

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जुलाई, 2021

MINIMUM WAGES IN DIFFERENT STATES

	U.P MINUMUM WAGES GENERAL /ENGINEERING			DELHI MINIMUM WAGES	RAJASTHAN MINIMUM WAGES	GUJRAT MINIMUM WAGES		PUNJAB MINIMUMWAGES	HARYANA MINIMUMWAGES	UTTARAKHAND MINIMUM WAGES	
	U.P. GENERAL	U.P. ENGG. BELOW 500	U.P. ENGG. ABOVE 500	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES	MINIMUM WAGES		MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	MINIMUMWAGES	
	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.		W.E.F.	W.E.F.	W.E.F.- 01/04/2021	
	01/04/2021 TO 30/09/2021	01/02/21 TO 31/07/2021	01/02/21 TO 31/07/2021	10/1/2020	8/1/2020	01/04/2021 TO 30/09/2021		3/1/2020	7/1/2020	For Adult Workers In Towns Of More Than One Lakh Population	For Remaining Parts Of The State
CATEGORY OF WORKERS	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC +DA	BASIC+DA	BASIC+DA	ZONE-I BASIC+DA	ZONE-II	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA	BASIC+DA
UN SKILLED	9073.02	10609.94	11123.32	15492.00	5850.00	9053.20	8845.20	9178.56	9458.20	9131.00	9013.00
SEMISKILLED	9980.32	11650.97	12235.65	17069.00	6162.00	9261.20	9053.20	9958.56	*	9724.00	9588.00
SEMISKILLED-A	*	*	*	*	*	*	*	*	9931.08	*	*
SEMISKILLED-B	*	*	*	*	*	*	*	*	10427.62	*	*
SKILLED	11179.54	12934.43	13347.99	18797.00	6474.00	9495.20	9261.20	10855.56	*	10318.00	10170.00
Clerical And Supervisory Staff NON MATRICULATE-(CLERICAL-1	*	*	*	17069.00	*	*	*	*	10949.01	11320.00	11128.00
Clerical And Supervisory Staff Matriculates But Not graduates / CLERICAL-2	*	*	*	18797.00	*	*	*	*	11496.47	10572.00	10411.00
Clerical And Supervisory Staff Graduates And Above	*	*	*	20430.00	*	*	*	*	*	*	*
HIGHLY SKILLED	*	*	*	*	7774.00	*	*	11887.56	12071.29	*	*

रंग लाई उद्यान विभाग की मेहनत, महापौर ने रोपे पौधे

–उद्योग विहार (जुलाई 2021)–

गाजियाबाद। जागृति विहार डिस्पेंसरी के सामने उपेक्षित पार्क के दिन बहुर गए हैं। यह पार्क पिछले लगभग 20 साल से अविकसित था। वहां अक्सर गंदगी की भरमार रहती थी। नगर निगम ने पार्क को विकसित करा दिया है। महापौर महापौर आशा शर्मा ने इस पार्क में पौधरोपण किया। उन्होंने वहां विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपित कराए। इसके पहले नगर निगम के उद्यान विभाग की टीम ने गंभीरता के साथ काम कर पार्क को साफ–सुथरा और खूबसूरत किया। इस पार्क पर काफी समय से विवाद चल रहा था। कुछ नागरिक पार्क का प्रयोग निजी कार्य के लिए कर रहे थे। इस कारण वहां गंदगी का अंबार रहता था। जबकि कुछ नागरिक पार्क को विकसित कराने को आतुर थे। इस विवाद को नगर निगम ने समाप्त करा दिया है। पार्क से अतिक्रमण भी हटाया गया है। कार्यक्रम के दौरान महापौर आशा शर्मा ने उपस्थित नागरिकों से एक–एक फलदार, छायादार एवं ऑक्सीजन देने वाला पौधा लगवाया। रोपित पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उधर, उप्र सरकार के नेतृत्व में शहर के सभी जनप्रतिनिधियों को स्वास्थ्य केंद्र गोद लेने थे। इसके तहत महापौर आशा शर्मा द्वारा जागृति विहार संजय नगर नवीन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया गया है। वहां उन्होंने पंखे, एयर कंडीशनर, बैंच एवं वाटर कूलर लगवाया था। डिस्पेंसरी के निरीक्षण के दौरान महापौर ने सामने के पार्क की खस्ता हालत को देखा था। इसके बाद पार्क की दशा में सुधार कराने के निर्देश दिए गए थे। महापौर ने रविवार को दोबारा डिस्पेंसरी का निरीक्षण किया इस मौके पर अमर दत्त शर्मा, विनीत शर्मा, पार्षद मोहन सिंह रावत, पार्षद कपिल शर्मा, अपर नगरायुक्त राज नारायण पांडे, नगर निगम के उद्यान अधिकारी डॉ. अनुज सिंह, जेई दिनेश शर्मा, मोनू त्यागी, रिषभ तिवारी, हरिदत्त आदि उपस्थित रहे।

वैक्सीन कम हुई तो केंद्रों पर लगने लगी लंबी कतार

–उद्योग विहार (जुलाई 2021)–

गाजियाबाद। जिले में वैक्सीन की कमी होने के साथ ही केंद्रों पर टीका लगवाने वालों की भीड़ उमड़ने लगी है। रामलीला मैदान घंटाघर और शास्त्रीनगर के टीकाकरण केंद्र पर भीड़ ने खूब हंगामा किया। पुलिस बुलानी पड़ी। रामलीला मैदान में तो आधा घंटे तक टीकाकरण रोकना पड़ा। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शास्त्रीनगर के केंद्र पर भी लोगों ने हंगामा किया। पोर्टल की गति धीमी होने की वजह से पंजीकरण में अधिक समय लगने से भी लोग परेशान हुए।

संयुक्त अस्पताल संजयनगर के केंद्र पर स्लाट बुक कराने के बाद पहुंचे युवाओं के पंजीकरण में तकनीकी अड़चन आ गई। आनन–फानन में पोर्टल पर सीधे पंजीकरण कराने पर सभी को टीका लगाया गया। विभाग के अनुसार करीब पांच हजार युवा पहली बार बिना टीकाकरण कराए केंद्रों से वापस लौटे हैं। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के पंजीकरण में भी पोर्टल पर परेशानी आने से टीकाकरण धीमा हो गया। अब केंद्रों पर तैनात रहेगी पुलिस टीकाकरण केंद्रों पर अब स्थानीय थाने की पुलिस तैनात रहेगी। प्रशासन, स्वास्थ्य एवं पुलिस के अधिकारियों ने संयुक्त वार्ता के बाद

तय किया है कि सुबह दस बजे से चार बजे तक पुलिस की एक टीम भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात रहेगी। कोई बेवजह हंगामा करता है तो उसे तुरंत थाने ले जाया जाएगा।

पिछले चार दिनों में सभी थानों से पुलिस बुलानी पड़ रही है। ऐसे में पुलिस की नियमित तैनाती का निर्णय लिया गया है। 35 केंद्रों पर 70 सत्र आयोजित जिले के सरकारी 35 टीकाकरण केंद्रों पर 70 सत्र आयोजित किए गए। दस निजी केंद्रों पर भी टीकाकरण किया गया। वैक्सीन के अभाव में टीकाकरण पचास फीसद हो गया है। कोरोनारोधी टीका जिले के 13,550 लोगों ने कोरोनारोधी टीका लगवाया। इनमें से 11,411 सरकारी और 2,139 लोगों को निजी केंद्रों पर टीका लगाया गया है।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.

❖LABOUR LAWS ❖HR MANAGEMENT
❖PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
❖SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

http://www.legalipl.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002

The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India

9818036460

legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
Editorial
03
P.
E-mail : udyogviharnp@gmail.com
गाजियाबाद, जुलाई, 2021

सम्पादकीय

चार लाख के पार

सत्येन्द्र सिंह

भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा चार लाख के पार निकल गया है। इतनी मौतें भले ही सवा साल के दौरान हुई हों, लेकिन मामूली नहीं है। देश में कोरोना से पहली मौत पिछले साल बारह मार्च को हुई थी। साढ़े छह महीने बाद एक अक्तूबर 2020 को यह आंकड़ा एक लाख पहुंच गया था और इस साल चौबीस अप्रैल को दो लाख तक। यानी एक लाख होने में दो सौ तीन दिन और एक से दो लाख होने में दो सौ आठ दिन लगे थे। पर इसके बाद चौबीस अप्रैल से बीस मई यानी तेईस दिन में ही मौतों का आंकड़ा बढ़ तक तीन लाख हो गया। फिर बीस मई से एक जुलाई यानी तियालीस दिन में एक लाख और लोगों ने दम तोड़ डाला। इन आंकड़ों का संबंध सिर्फ इस बात तक ही सीमित नहीं है कि कितने दिन में कितनी मौतें हुईं, बल्कि इस महामारी की भयावहता, संकट से निपटने की हमारी तैयारियों और लापरवाहियों की ओर भी ध्यान खींच रहा है। तेईस दिन में एक लाख लोगों की मौत बता रही है कि तेरह महीने में दो लाख लोगों की मौत से हमने कोई सबक नहीं लिया। अगर कुछ सीखा होता, सतर्कता दिखाई होती, अस्पतालों का ढांचा मजबूत बनाया होता, केंद्र और राज्यों में बेहतर तालमेल होता, टीकाकरण अभियान की रणनीति दमदार होती तो मौतों का आंकड़ा चार लाख के पार जाने से रोका जा सकता था।

अब रोजाना संक्रमण के मामले पचास हजार से नीचे आ गए हैं। रोजाना मौतों का आंकड़ा भी नौ सौ से कम दर्ज हो रहा है। संक्रमण दर की बात करें तो यह 2.34 फीसद है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अब संक्रमण का रुझान उतार पर है। लेकिन विशेषज्ञों की इस चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि खतरा अभी बरकरार है। चौदह राज्यों के अस्सी जिलों में संक्रमण दर दस फीसद से ऊपर बनी हुई है। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि तीसरी लहर का खतरा सामने है। कोरोना विषाणु के नए स्वरूप डेल्टा प्लस के मामलों का मिलना बता रहा है कि एक और बड़ा खतरा दस्तक दे चुका है। कवक संक्रमण के बढ़ते मामले हैरान करने वाले हैं। ऐसे में यह मान लेना कि अब हम महामारी से मुक्ति की ओर हैं, हमारा मुगालता ही होगा।

भारत में कोरोना से हुई मौतों के मामले में यह तर्क देना या मान लेना कि आबादी को देखते हुए दूसरे देशों के के मुकाबले हमारे यहां काफी कम लोग मरे हैं, ठीक नहीं है। इसी तरह दुनिया में सबसे ज्यादा या एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण को लेकर भी दावे किए जाते रहे हैं। पर इन दावों के बजाय जमीनी हकीकत को स्वीकार करने की जरूरत है।

इस सच्चाई से कोई भी मुंह नहीं मोड़ेगा कि देश में टीकाकरण की रफ्तार निराशाजनक ही रही है। वरना क्या कारण रहा कि इक्कीस जून को पिच्यासी लाख टीके लगने का दावा किया गया और उसके बाद से यह आंकड़ा पचास से साठ लाख भी मुश्किल से छू पा रहा है। ताजा स्थिति यह है कि ज्यादातर राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं। इससे रोजाना का टीकाकरण लक्ष्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित ऐसे कई राज्य हैं।

जाहिर है यह कहीं न कहीं टीकों के उत्पादन और राज्यों को आपूर्ति से जुड़ा मामला है जो कुप्रबंधन और अदूरदर्शी नीतियों का शिकार हो चुका है। इसे दुरुस्त किए बिना हम कैसे महामारी से जंग जीत पाएंगे, यह बड़ा सवाल है।

पारदर्शी प्रशासन का संकल्प आधा-अधूरा क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता संभाले आठवां साल चल रहा हैं। बीते सात सालों में मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। किस तरह से इस राजनीतिक इच्छाशक्ति वाली सरकार ने अपने फैसलों से राजनीति की दशा-दिशा बदली है, यह एक उदाहरण बना है। लेकिन प्रशासन को पारदर्शी, ईमानदार एवं कार्यकारी बनाने के मोदी सरकार के संकल्प अभी आधे-अधूरे ही पड़े है। जिसे गुड गवर्नेस कहा जाता है, उसके लिए जरूरी है कि ह्यसबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वासह्ल पर चलने वाली सरकार अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही प्रशासन-व्यवस्था में बदलाव लाए। मोदी सरकार ने प्रशासनिक सुधार के भी काम बड़े पैमाने पर किए गए हैं, उसका लाभ भी देश को दिख रहा है। प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए हाल के वर्षों में भाजपा सरकार ने अनेक सार्थक कदम उठाये हैं। मोदी सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि न तो भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जायेगा और न ही भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा जायेगा। बात केवल भ्रष्टाचार की नहीं है, सरकारी कामों में बिचौलियां एव दलाल व्यवस्था कायम रहने की भी है। बड़ी परेशानी का सबब है इस व्यवस्था का कायम रहना और इसका वर्चस्व बढ़ना, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आम-जनता के द्वारा सीधे काम करवाने के लिये तत्पर होने पर उनके काम लटकाना, बार-बार चक्कर लगावना, तरह-तरह के डोक्यूमेंट की मांग करना आदि ऐसी समस्याएं मोदी सरकार में पहले से ज्यादा बढ़ी है। नेताओं से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक यह स्वर साफ सुनने को मिल रहा है कि बिना धन के पहिये की गाड़ी आगे नहीं सरकती, सरकारें कितने ही आदर्शवाद के नारे लगाये, कितनी ही कड़ी कार्रवाई का भय दिखाये- भ्रष्ट प्रशासन कायम रहेगा। ये सारे मामले न सिर्फ गंभीर हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था को खोखला करने वाले हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2018 की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी भाजपा सरकार अपने पिछले कार्यकाल से ही सरकारी दफ्तरों के कामकाज में सुधार लाने के प्रयास करती रही है। इसके लिए उसने कई कदम भी उठाए हैं, जिसमें हर कर्मचारी के समय पर दफ्तरों में पहुंचने और उनके काम करने पर निगरानी का तंत्र विकसित किया गया। उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की गई। इन कारणों से थोड़ा-बहुत सुधार हुआ भी है, तो वह बहुत ऊंचे स्तर पर, लेकिन कुल मिलाकर इतना अप्रभावी कि उसे ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। कठोर नियंत्रण एवं नीतियों के बावजूद प्रशासनिक कार्यों में भ्रष्टाचार व्याप्त होना विडम्बनापूर्ण है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रिश्वतखोरी कायम है, दलालों का बोलबाल है। सभी सरकारी प्रक्रियाएं जटिल है, डीडीए में फ्लैट को फ्रीहोल्ड कराने की प्रक्रिया को ही ले लीजिये इतनी जटिल एवं असंभव सरीकी है कि बिना दलालों के यह संभव नहीं हो पाती। मेरे मित्र ने साहस करके बिना दलालों के खुद ही फ्रीहोल्ड कराने की ठानी, लेकिन दो साल से अधिक समय बीत जाने एवं बीसों चक्कर लगाने, समस्त औचारिकताएं पूरी करने के बावजूद उनका फ्लैट फ्रीहोल्ड नहीं हो पाया है, कैसे आम नागरिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के न खाऊंगा और न खाने दूंगा एवं प्रशासन में दलाली एवं एजेंट प्रथा के समाप्त होने की घोषणाओं पर विश्वास करें? पुलिस हो या अधिकारी आज भी नोट जुगाड़ने की कोशिश में रहते हैं, जनता की सेवा एवं सहयोग के लिये नहीं। जनता परेशान होगी तभी तो रिश्वत देगी, यह भ्रष्टाचार शासन एवं प्रशासन की जड़ों में पेठा हुआ है, इन विकट एवं विकराल स्थितियों में एक ही पंक्ति का स्मरण बार बार होता है, घर-घर में है रावण बैठा इतने राम कहां से लांऊ। भ्रष्टाचार, बेईमानी और अफसरशाही इतना हावी हो गया है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है।

राशन कार्ड बनवाना हो, ड्राइविंग लाइसैंस बनवाना हो, डीडीए में मकान/फ्लैट को फ्रीहोल्ड करवाना हो, चालान जमा देना हो, स्कूल में प्रवेश लेना, सरकारी अस्पताल में इलाज कराना हो और यहाँ तक की सांस लेना हो तो उसके लिए भी रिश्वत की जरूरत पड़ती है। कोरोना महामारी की संकटकालीन स्थितियों में भी यह भ्रष्टाचार बढ़-चढ़ कर सामने आया है। समस्याओं से जूझते हुए कब तक हम लोग नरेंद्र मोदी को ढूंढते फिरेंगे? कब तब इन नेताओं की भ्रष्टाचारमुक्त त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई की घोषणाएं केवल नारों तक सीमित रहेगी? आखिर कब प्रशासन नींद से जागेंगे? नेताओं के संकल्पों को आकार देने की कुछ जिम्मेदारी तो प्रशासनिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भी है। 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने नौकरशाहों पर नकेल कसने की खुलेआम घोषणा की थी। नरेन्द्र मोदी ने हालांकि बारह साल तक सफलतापूर्वक गुजरात का प्रशासन नौकरशाहों की ही मदद से चलाया था, किंतु लगता है कि इस संतोषजनक अनुभव के बावजूद उनके मन के किसी कोने में कहीं कोई छोटा सा ही सही, लेकिन संदेह था। इसलिए प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने घोषणा की कि ह्यअब मेरा क्या, मुझे क्याह्ल नहीं चलेगा। उनके प्रभावी शासन की चचाएं बहुत दूर-दूर तक हैं यह अच्छी बात है लेकिन इन चचाओं के बीच हमारे देश का भ्रष्टाचार एवं सरकारी कामों के लेट लतीफ, काम लटकाने की मानसिकता भी दुनिया में चर्चित है, इसे तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमें जरूरत है इसको रोकने की। हमें यह कहते हुए शर्म भी आती है और अफसोस भी होता है कि हमारे पास ईमानदारी नहीं है, राष्ट्रीय चरित्र नहीं है, नैतिक मूल्य नहीं है, काम के प्रति जबावदेही नहीं है। आज का काम कल पर टालने की मानसिकता एक आम आदमी को कितने सरकारी कार्यालयों के चक्कर कटवाती है, जगजाहिर है। राष्ट्र में जब राष्ट्रीय मूल्य कमजोर हो जाते हैं और सिर्फ निजी स्वार्थ और निजी हैसियत को ऊंचा करना ही महत्वपूर्ण हो जाता है तो वह राष्ट्र निश्चित रूप से कमजोर हो जाता है और नकारों, भ्रष्टाचारियों का राष्ट्र बन जाता है।

मृदुला घई

लेखक परिचय :
अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
साहित्यिक रुझान के चलते हिंदी की कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। इनकी काफी रचनाएँ औरतों और शोषित वर्गों के मुद्दों को बखूबी बयां करती हैं। 'यमुना', 'कल्लो', 'सच', 'उड़ान', 'बाल विधवा', 'बेटी', 'सती', 'बुनकर', 'देश के पत्रकार' इत्यादि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएँ हैं। हाल ही में उनकी रचना 'देश के पत्रकार' बहुत सारे समाचार पत्रों में छपी है और सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। उर्दू के कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी कई रचनाओं का अनुवाद छपा हैं।

कविता

बेटी

जन्मा एक पत्थर ने
एक पत्थर का टुकड़ा
मुझार्या सबका मुखड़ा
एक ही दुखड़ा
और गहरी टीस
जमाने की रीस
हुआ कुछ ना दुआ से
माँगा था बेटा खुदा से
पर आई लड़की कम्बखत
फुट गई किस्मत

समय ने ली करवट
हटी दिल की सलवट
पत्थर से बनी परी
किलकारियों की झड़ी
पायल की झंकार
हंसी की खनकार
चहकता घर द्वार
उसी की पुकार
नन्हे नन्हे पावं
प्यार की छावं
नाजो का पलना
बचपन का ढलना
संभालना व फिसलना
किया खुद से दुर
फिर निभाया दस्तुर
फिर जन्मा एक पत्थर ने
एक पत्थर का टुकड़ा
मुझार्या हर मुखड़ा
उमड़ा वही दुखड़ा
हाये कैसा व्यापार हुआ
कैसा ये दुराचार हुआ
ना जाने कितने पैगाम दिए
भर भर पैसे थाम दिये
फिर भी इक दिन
डायन का इल्जाम हुआ
परी का सपना खाक हुआ
दिल का दुकड़ा राख हुआ
इक एहसास हुआ
लाड दिया प्यार दिया
पैसा सिर से वार दिया
ना शिक्षा दी ना ज्ञान दिया
कच्ची उम्र में ब्याह दिया
हाय ये क्या किया
दिल दहला दिया

विचार-विमर्श किया
खूब संघर्ष किया
कटे पंख उगे
सोये सपने जगे
नई उड़ान मिली
खूब शान बढ़ी
ना कष्ट सहा
न पत्थर रहा
आई जीवन ललक
मिली नई झलक
मांगी बेटी खुदा से
उसकी सदा से
नव जीवन सचांर
सूंदर सुखी संसार
परियो सा प्यार
बेटी से ही
महकता घर द्वार

TAKSHAK
MANAGEMENT INDIA PVT LTD
EVENTS MANAGEMENT
PR MANAGEMENT
ARTISTS MANAGEMENT
http://www.takshakindia.com
BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.-201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C,
Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
takshakindia@gmail.com

उद्योग विहार

निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र

04 P.

E-mail : udyogviharnp@gmail.com

गाजियाबाद, जुलाई, 2021

विकास कार्यक्रमों एवं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए

आयुक्त मेरठ मंडल ने किया सघन दौरा

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

गाजियाबाद। मंडल आयुक्त मेरठ मंडल सुरेंद्र सिंह के द्वारा जनपद के विकास कार्यक्रमों एवं कोरोना की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से जनपद गाजियाबाद का गहन स्थल निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त ने अपने भ्रमण के दौरान प्रथम चरण में मसूरी पहुंचकर मत्स्य विभाग द्वारा आयोजित मत्स्य बीज संचय कार्यक्रम में भाग लिया। यहां पर उन्होंने मत्स्य विभाग की लगभग 20 हेक्टेयर की मत्स्य झील में मत्स्य बीज संचय किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशासनिक एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार का यह बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। अतः मत्स्य झील के सौंदर्यकरण का कार्य प्रमुखता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए। ज्ञातव्य हो कि संबंधित मत्स्य झील से सरकार को प्रत्येक वर्ष लगभग 11 लाख रूपए का राजस्व प्राप्त होगा। झील के सौंदर्य करण कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनपद वासियों को वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से कमिश्नर के द्वारा यहां पर वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के द्वारा भी पौधा रोपित किया गया। मंडला आयुक्त ने अपने भ्रमण के दूसरे चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डासना एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर में पहुंचकर गहन स्थल निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई सभी प्रकार की तैयारियां सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष में कोरोना को लेकर जनपदवासियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बनाने एवं सरकार की मंशा के अनुरूप संक्रमित व्यक्तियों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप इलाज संभव कराने के क्रम में जनपद गाजियाबाद के प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है अतः कोरोना की तीसरी लहर को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दृढ़ता के साथ अपनी तैयारी सुनिश्चित की जाए ताकि तीसरी लहर आने पर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का सरकार की मंशा के अनुरूप निर्धारित प्रोटोकाल के आधार पर इलाज संभव कराया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना के संक्रमित व्यक्तियों की संख्या जनपद में नगण्य है। प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर वर्तमान में तैयारी करने के संबंध में पर्याप्त समय उपलब्ध है सभी अधिकारी गण अपने अपने स्तर पर तैयारी सुनिश्चित कर लें। मंडलायुक्त ने अपने भ्रमण के दौरान दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान नियमित स्तर पर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित करते हुए उनका लाभ नागरिकों तक पहुंचाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जनपद के सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि सरकार की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों को सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना को लेकर संचालित किए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बहुत ही दृढ़ता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सरकार के इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक नागरिक लाभ प्राप्त कर सकें। कमिश्नर ने अपने भ्रमण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध में भी आवश्यक संदेश प्रदान किए। मंडलायुक्त के भ्रमण के दौरान जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी अस्मिता लाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनके गुप्ता अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

एनडीआरएफ में बढ़ेगी हरियाली, लगाए गए पौधे

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

गाजियाबाद। 8वीं बटालियन एनडीआरएफ परिसर कमला नेहरू नगर मे पौधरोपण अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर विभिन्न प्रकार के छायादार एवं फलदार पौधे रोपित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री अतुल गर्ग रहे। उन्होंने एनडीआरएफ के कार्यों की प्रशंसा कर पौधरोपण कार्यक्रम को समय से जरूरत बताया। कमांडेंट पीके तिवारी ने बताया कि 8वीं बटालियन एनडीआरएफ हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर रहती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से परिसर में 500 से ज्यादा फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाकर पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही आपदाओं की संख्या में कमी ला सकते हैं। एनडीआरएफ पर्यावरण और आपदा के बीच के रिश्ते को बखूबी समझती है। प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य स्त्रोत पर्यावरण से छेड़छाड़ है। आपदाओं के लिए सिर्फ प्रकृति को जिम्मेदार ठहराने की बजाय हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कोरोना महामारी ने ऑक्सीजन के महत्व को समझाया है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके।

❑ 8वीं बटालियन एनडीआरएफ हमेशा पर्यावरण संरक्षण के लिए तत्पर रहती है : कमांडेंट पीके तिवारी

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (परिवार एवं स्वास्थ) अमित मोहन प्रसाद, जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सीडीओ अस्मिता लाल, डीएफओ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर उमाकांत तिवारी आदि मौजूद रहे।

4925 दिव्यांगों को बिना सत्यापन के मिलेगी पेंशन

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

नोएडा। जनपद में रहने वाले दिव्यांग पेंशनधारियों के खातों में बिना सत्यापन के पेंशन पहुंच जाएगी। जिले में 4925 दिव्यांग, 9542 निराश्रित और 20600 वृद्धा पेंशन धारक हैं। इन्हें दिव्यांग कल्याण, प्रोबेशन विभाग व समाज कल्याण विभाग की तरफ से पेंशन मिलती है, जिसका साल में दो बार सत्यापन कराया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में पंचायत चुनाव व कोरोना के कारण सत्यापन नहीं हो सका। जब शुरूआत हुई तो समय कम मिला। 30 जून तक नगर और ग्रामीण इलाकों की पेंशन का सत्यापन करना था, जिसमें आखिरी दिन तक करीब 70 फीसदी तक सत्यापन किया जा सका। सत्यापन के आधार पर ही धनराशि दी जाती है। मगर इस बार सत्यापन न होने के कारण इन लोगों का पेंशन अभी तक नहीं मिली थी। पेंशनरों को परेशानी न हो, इसके लिए बिना सत्यापन के दिव्यांग कल्याण विभाग को निदेशालय ने इस वर्ष की पहली किस्त जारी कर दी है, जो खातों में जुलाई के पहले सप्ताह में भेज दी जाएगी।

डीएमई ने रोका इंटरनेट, गजियाबाद व मेरठ के 250 गांव हुए प्रभावित

-उद्योग विहार (जुलाई 2021)-

गाजियाबाद। डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट योजना शुरू की गई थी। जिले के तमाम गांवों को योजना के तहत फाइबर केबल से जोड़ा गया। लेकिन इस बीच मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे(डीएमई) का निर्माण शुरू हुआ तो

❑ सीवरेज को लेकर खुदाई के चलते मोदीनगर में बीएसएनएल की सेवायें ठप्प, वाहनों की रफतार थमी

वही मोदीनगर में सीवरेज लाईन बिछाने को लेकर जगह-जगह खुदाई व एनसीआरटीसी की ओर से रैपिड रेल निर्माण कार्य को लेकर विधुत पोल शिफिटिंग व गडढो के कारण बीएसएनएल की केबल ओर फाइबर केबल क्षतिग्रस्त हो गया। इस कारण गाजियाबाद के तकरीबन 60 तथा मेरठ व उसके आस-पास के 150 गांवों का इंटरनेट बाधित हो गया है। कई बार पत्रचार के बाद दिक्कत को दूर नहीं किया जा सका है। केंद्र की मोदी सरकार ने छह साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरूआत कर हर गांव को भारत नेट योजना से जोड़ने की योजना शुरू की। योजना के तहत गांव-गांव को फाइबर नेट के माध्यम से जोड़ा गया और ग्रामीणों को सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराया जाना था। तब जनपद के करीब 161 गांवों में फाइबर केबल डालकर उन्हें योजना से जोड़ा जाना था। अधिकांश गांवों को योजना से जोड़ दिया गया। इस बीच करीब दो साल पहले दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के चलते भोजपुर ब्लॉक के तकरीबन 40गांवो में फाइबर केबल क्षतिग्रस्त हो गया। केबल क्षतिग्रस्त होने से अब काफी समय से इन गांवों की इंटरनेट सेवा बाधित है। वहीं मोदीनगर में सीवरेज लाईन बिछाने के कार्य तथा रैपिड रेल के लिये अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिये जमीन की हुई खुदाई से जगह जगह बीएसएनएल की केबिल कट गयी है। जिस कारण शहर के पालिका के 26 वार्डो में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा बाधित है। तो वही तकरीबन आस पास के 20 गांव का भी यही बुरा हाल है।

लापरवाही से दूर हुआ लाभ

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सस्ता इंटरनेट मिलने, जनसेवा केंद्र खुलने, डिजिटल सेवा केंद्र आदि का लाभ नहीं मिल सका है। योजना से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जोड़कर लाभ दिया जाना था। लेकिन सेवा बाधित होने के कारण डिजिटल सेवा केंद्र खुलने से पहले ही बंद हो गए हैं। वही इंटरनेट की सेवाये बाधित होने पर ऑनलाईन बच्चो की पढाई का कार्य भी बाधित हो रहा है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान फाइबर केबल क्षतिग्रस्त हो जाने से मोदीनगर व एक्सप्रेस वे के आस पास के गांवों की इंटरनेट सेवा बाधित है। कार्यदायी संस्थाओ को क्षतिपूति के दाँवे के लिये पत्र लिखा गया है। शीघ्र ही समस्या का निदान कराया जाएगा।

सपना गुप्ता, दूरसंचार तकनीकी अधिकारी, (डीईटी) मोदीनगर टेलीफोन एक्सचेंज

सीएम, पीएम की गांववासियों को हाईटेक योजनाओं की स्थिति

-161 गांवों को भारत नेट से जोड़ने का लक्ष्य
-131 गांवों को फाइबर केवल डालकर जोड़ा
-40-50 गांवों में ही चल रहा है इंटरनेट
-मोदीनगर शहर व बीस गांवों की इंटरनेट सेवा है वर्तमान में बाधित

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी-9, सैक्टर-3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.-243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120-4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह